भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2077
उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

आरयूएसए और पीएम-यूएसएचए

2077. श्री अभय कुमार सिन्हा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तीसरे चरण के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;
(ख) क्या प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) में बिहार को शामिल नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) शिक्षा के मामले में बिहार का स्थान क्या है;
(घ) क्या सरकार का उक्त योजनाओं के अंतर्गत बिहार को शामिल करने का विचार है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ड): मंत्रालय ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। पीएम-यूएसएचए के तहत, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा विभिन्न घटकों के अंतर्गत 5613.12 करोड़ रुपये की कुल राशि के साथ 440 इकाइयों को अनुमोदित किया है। अनुमोदित राशि का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। बिहार ने राज्य में पीएम-यूएसएचए को कार्यान्वित करने के लिए हाल ही में दिनांक 25.07.2024 को मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद, बिहार को पीएम-यूएसएचए योजना में शामिल कर लिया गया है।

बिहार राज्य का उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 28.4 के राष्ट्रीय जीईआर के मुकाबले 17.1 है।

*****

अनुलग्नक

आरयूएसए और पीएम-यूएसएचए के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा द्वारा दिनांक 05.08.204 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2077 के भाग (क) से (ड.) उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पीएम-यूएसएचए के अंतर्गत अनुमोदनो का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित इकाइयों की संख्या	कुल अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	3.43
2	आंध्र प्रदेश	25	274.99
3	अरुणाचल प्रदेश	5	45.00
4	असम	19	229.96
5	चंडीगढ़	1	5.00
6	छत्तीसगढ	16	214.88
7	गोवा	2	104.99
8	गुजरात	32	425.00
9	हरियाणा	१३	96.26
10	हिमाचल प्रदेश	7	154.76
11	जम्मू और कश्मीर	9	70.00
12	झारखंड	20	234.79
13	कर्नाटक	30	413.98
14	लद्दाख	2	23.86
15	मध्य प्रदेश	38	565.00
16	महाराष्ट्र	58	791.18
17	मणिपुर	4	24.99
18	मेघालय	3	15.00
19	मिजोरम	3	20.00
20	नागालैंड	4	25.00
21	पुदुचेरी	1	5.00
22	पंजाब	१३	85.00
23	राजस्थान	33	320.00
24	सिक्किम	4	40.00
25	तेलंगाना	18	225.00
26	त्रिपुरा	5	45.00
27	उत्तर प्रदेश	66	995.06
28	उत्तराखंड	8	160.00

*****